भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3868

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

शैक्षिक पहलों के कार्यान्वयन का प्रभाव

†3868. **श्री कामाख्या प्रसाद तासा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 3,656 स्कूलों के उन्नयन से कितने छात्रों और शिक्षकों को सीधे लाभ हुआ है;

(ख) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम-पोषण) ने वंचित और अल्पलाभप्राप्त समुदायों को शिक्षा में सम्मिलित करने में किस प्रकार योगदान दिया है;

(ग) ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां 'समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ (उल्लास)' विशेष रूप से सफल रही है और उस सफलता में कौन कौन से कारकों ने योगदान दिया है;

(घ) सरकार द्वारा स्कूलों में इको क्लबों की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम- श्री) स्कूलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): वर्ष 2018-19 से वर्ष 2024-25 तक अपग्रेड किए गए स्कूलों की सूची इस प्रकार है:

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2024-25 तक अपग्रेड किए गए स्कूलों की संख्या	**इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक नामांकन**	**इन विद्यालयों में शिक्षक**
3680	644038	33207
स्रोत- अपग्रेड किए गए स्कूलों की संख्या प्रबंध से ली गई है (फरवरी, 2025) और नामांकन और शिक्षक जानकारी यूडाइज़+ 2023-24 से हैं।		

(ख): **पीएम पोषण** योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाती है एवं इसमें सरकारी तथा सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बालवाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) और कक्षा 1-8 तक के सभी बच्चे शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत में अधिकांश बच्चों की दो गंभीर समस्याओं, भूख और शिक्षा का समाधान करना है:

i) सरकारी एवं सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) और कक्षा 1-8 तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में बिना किसी भेदभाव के सुधार करना।

ii) वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना तथा कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी सहायता करना।

iii) ग्रीष्मावकाश एवं आपदा के समय सूखा/आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

(ग): **उल्लास**: भारत सरकार वित्त वर्ष 2022-23 से उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है जिसका अर्थ है समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसरण में, यह योजना 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन निरक्षरों को लक्षित करती है, जो औपचारिक स्कूल शिक्षा से चूक गए हैं। इस योजना को हाइब्रिड मोड में लागू किया गया है, जिससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑफ़लाइन, ऑनलाइन या मिश्रित तरीकों को अपनाने की सुविधा मिलती है। उल्लास भारत को **'जन-जन साक्षर'** बनाने की संकल्पना पर आधारित है, जो कर्तव्यबोध (कर्तव्य की भावना) से प्रेरित है, जिसमें स्कूल/उच्चतर शिक्षण संस्थानों के प्लेटफॉर्म का उपयोग और स्वयंसेवा के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी शामिल है। शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों के पंजीकरण के लिए एक समर्पित उल्लास मोबाइल ऐप विकसित किया गया है और यह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को भी सक्षम बनाता है।

यह योजना पश्चिम बंगाल और बिहार को छोड़कर देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। उल्लास मोबाइल ऐप पर कुल 2,20,48746 शिक्षार्थी और 40 लाख से अधिक स्वयंसेवी शिक्षक पंजीकृत हैं। उल्लास योजना के अंतर्गत आयोजित आधारभूत साक्षरता संख्याज्ञान मूल्यांकन परीक्षा में 1.28 करोड़ से अधिक नव-साक्षर/लाभार्थी शामिल हुए। यह योजना देश के सभी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की जा रही है। लद्दाख ने जून 2024 में पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है। इन क्षेत्रों की सफलता का श्रेय सरकारी नीतियों, सामुदायिक भागीदारी, तकनीकी एकीकरण, लक्षित शिक्षण कार्यक्रमों और समावेशी पहुँच संबंधी प्रयासों के संयोजन को दिया जा सकता है।

(घ): **इको क्लब** स्कूलों में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करते हैं, जो छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के लिए व्यावहारिक कौशल और ज्ञान विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। जल उपयोग को इष्टतम बनाने, अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करने, पुनर्चक्रण करने, तथा वृक्षारोपण अभियान चलाने जैसी गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से, छात्र स्थायी पद्धतियों का अधिगम करते हैं, जिन्हें वे स्कूल के भीतर तथा बाहर दोनों जगह क्रियान्वित कर सकते हैं। इको क्लब छात्रों को पर्यावरण राजदूत के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त बनाते हैं तथा पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार जैसे एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करना, जल संरक्षण करना और पर्यावरण-अनुकूल पहलों में भाग लेने को बढ़ावा देकर अपने परिवारों और समुदायों तक अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को हमारे ग्रह को संरक्षित और सुरक्षित रखने की साझा जिम्मेदारी की गहन समझ प्राप्त होती है, जिससे एक स्थायी भारत के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों को पोषित करने के एनईपी 2020 के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इको क्लबों की गतिविधियों को मिशन लाइफ के साथ एकीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनका नाम बदलकर "इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ" कर दिया गया है। इको क्लब की सभी गतिविधियों को मिशन लाइफ (ऊर्जा बचाओ, जल बचाओ, एकल प्लास्टिक उपयोग को ना कहो, टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को अपनाओ, अपशिष्ट को कम करो, स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ और ई-कचरा कम करो) के सात विषयों के अनुरूप बनाया गया है।

(ङ) **पीएम श्री योजना** के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से 12,505 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया जा चुका है। पीएम श्री स्कूलों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना है तथा साथ ही इन स्कूलों को एनईपी 2020 के विभिन्न घटकों के साथ जोड़ते हुए पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। इनमें कंप्यूटर लैब/आईसीटी लैब/स्मार्ट क्लासरूम, व्यावसायिक कौशल शिक्षा, इंटरनेट सुविधा, पुस्तकालय, पूरी तरह सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला /जीव विज्ञान प्रयोगशाला, भली-भांति सुसज्जित खेल सुविधा-युक्त खेल का मैदान, ग्रीन स्कूल सुविधाएं, स्कूल इनोवेशन काउंसिल, मिशन लाइफ के लिए कार्यात्मक युवा और इको क्लब, स्कूल प्रधानाचार्यों/शिक्षकों का क्षमता निर्माण और प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए जादुई पिटारा, छात्रों के लिए 10 बैगलेस दिवस आदि शामिल हैं।

*****